सतना, शुक्रवार 22 अगस्त 2014

नान कारपोरेट सेक्टर की उपेक्षा, होगा आन्दोलन

स्टार समाचार | सतना

देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों के लिए अगले दो माह में देश के अलग-अलग हिस्सों में जन अदालतें लगाई जायेंगी तथा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जायेंगे। जिसमें छोटे-छोटे व्यापारियों की आवश्यकताओं का जाना जायेगा। देश के व्यापारियों की शीर्ष संस्था कम्फेडरेशन आफ आल इण्डिया टेडर्स (दिल्ली) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार गोलमेज सम्मेलनों में वित्तीय व बैंकिंग विशेषज्ञों की रायशुमारी लेकर एक नीति बनाई जायेगी। उसके पश्चात श्वेत पत्र जारी करते हुए भारत सरकार को सौंपा जायेगा। संस्था की राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खण्डेलवाल द्वारा जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान और देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र को कर्ज देने में बैंक और सरकार असफल रही है।

इसके बावजूद असंगठित व्यापारी कारपोरेट सेक्टर से आगे निकल गया है। छोटे व्यापार की सुदृढ़ ऋण व्यवस्था के लिए वित्त मंत्रालय लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय एवं रिजर्व बैंक के अधिकारियों की एक कमेटी बनाने के लिए एक्शन कमेटी का गठन किया गया है जो विभिन्न बिन्दुओं पर रायशुमारी कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपेगी।

कम्फैडरेशन आफ आल इण्डिया टेडर्स कैट सतना के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार दौलतानी के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय टीम के द्वारा लिए गए निर्णयानुसार व्यापारियों की वित्तीय व ऋण संबंधी परेशानियों को जानने के लिए देश के 30 जनपदों में जन अदालत लगाई जायेगी और 10 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जायेंगे जिसमें वित्तीय विशेषज्ञ, बैंकिंग विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठेंगे और असंगठित व्यापारियों के लिए नए वित्तीय ढांचे का स्वरूप तय करेंगे। रायशुमारी के बाद श्वेत पत्र जारी किया जायेगा जो एक्शन कमेटी के माध्यम से भारत सरकार को सौंपा जायेगा।